अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए संस्थाओं को अनुदान

2223. **श्री सुनील कुमार चट्टनायक :** क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन संस्थाओं के नाम क्या हैं जिनको अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कल्याण कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुदान प्रदान किए गए हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक संस्था को कितनी-कितनी धनराशि का अनुदान दिया गया हैं ;

(ख) उन संस्थाओं के नाम क्या-क्या हैं जिनके अनुदान से संबंधित मामलों को अस्वीकार कर दिया गया है और उनके अनुदान के मामलों को अस्वीकार किए जाने के क्या कारण हैं ;

(ग) ऐसी संस्थाओं के कार्यकर्ताओं और कर्मचारियों के नाम क्या-क्या हैं ; और

(घ) उक्त संस्थाओं से लाभ प्राप्त करने वाले व्यक्तियों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री ओ. राजगोपाल (अरकोनम) : (क) सूचना अनुबंध में दी गई है। [देखिए, परिशिष्ट – 153, अनुबंध संख्या 93]

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान ऐसे स्वैच्छिक संगठन का कोई मामला अस्वीकार नहीं किया गया था।

(ग) और (घ) मांगी गई सूचना उपलब्ध नहीं है। सभी स्वैच्छिक संगठनों से लाभ प्राप्त कर रहे कार्यकर्त्ता, कर्मचारियों और व्यक्तियों के नाम प्राप्त करना कठिन होगा। कार्यकर्त्ताओं, कर्मचारियों और लाभप्राप्तकर्त्ताओं की स्वैच्छिक संगठन-वार, श्रेणी-वार संख्या एकत्र की जा रही हैं और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

Cut in working hours

2224. **SHRI PRAMOD MAHAJAN:** Will the Minister of LABOUR be pleased to state whether Government agree to the proposal of International Labour organisation of cutting the working hours in factories and thus creating more jobs for the labour which appeared in The Daily, Bombay, March 7, 1990?

THE MINISTER OF LABOUR AND WELFARE (SHRI RAM VILAS PASWAN): As mentioned in the News-item to which reference has been made, it has been stated in the ILO report that it is difficult to assess the real impact of working time reduction on employment and that various studies have come to different conclusions. As the ILO report has not made any conclusive and categorical proposal, the question of agreeing or not agreeing to it does not arise.

Withdrawal of cases against the residents of Indira Nagar, Delhi

2225. **SHRI SOHAN LAL DHUSIYA:** Will the Minister of URBAN DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) whether Government propose to withdraw the cases filed against the residents of Indira Nagar, Delhi-33 by the Municipal Corporation of Delhi for violating certain paper formalities in the matter of constructing/reconstructing/renovating the houses; if so, the details thereof;

(b) whether Government are aware that construction work is still going on in that colony without any permission; and

(c) what action Government propose to take against the erring officials for allowing such illegal constructions?

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI MURASOLI MARAN): (a) The M.C.D. has reported that there is no such proposal with them.

(b) and (c) As and when any unauthorised construction is noticed, M.C.D. takes action as per law and policy. If any lapse is found appropriate action is taken against the erring officials.